अपने साधनों से नदियों को जोड़ेगी सरकार

संजय झा ने सदन में की घोषणा, जून तक बोधगया, राजगीर, नवादा में गंगा से पेयजल की आपूर्ति

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार अब अपने साधनों से भी नदियों को जोड़ने की योजना चलाएगी। फिलहाल उत्तर एवं दक्षिण बिहार की तीन-तीन नदियों को जोड़ने की योजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को विधानसभा में यह घोषणा की।

सदन ने जल संसाधन विभाग के चार हजार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक के बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि फरक्का में अगस्त तक स्पर डैम का निर्माण पूरा हो जाएगा। इससे नदी में पानी की उपलब्धता रहेगी। जून तक गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया, राजगीर एवं नवादा में पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मोकामा में ईंटर लेवल बन गया है। मोटर लगा दिया गया है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में विभाग की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य हासिल किए गए। बाढ़ सुरक्षात्मक उपायों के जरिए इससे होने वाली क्षति को नियंत्रित किया गया।

विधानसभा में जल संसाधन विभाग का बजट पेश करते मंत्री संजय झा। सदन की कार्यवाही में भाग लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (दाएं से), उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव व अन्य सदस्यगण। ● जागरण

जीवित हो रहीं पुरानी नदियां

मंत्री संजय झा के मुताबिक मृत पड़ी लखनदेई नदी को जीवित किया गया है। गाद निकाल कर उसकी पुरानी धार कायम हो रही है। योजना यह भी है कि नदियों के अतिरिक्त पानी को उन इलाकों में दिया जाए, जहां इसकी जरूरत है। बेलवा धार में इंटर लिंकिंग का 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कमला का अधिशेष पानी बूढ़ी गंडक में डाला जाएगा। इससे दो हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का होगा सृजन

मंत्री ने बताया कि दुर्गावती कमांड क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि 32 हजार चार सौ 67 हेक्टेयर है। 3247 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत काम चल रहा है। इसी तरह उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का काम पूरा हो जाने से वर्तमान सिंचाई क्षमता 56 हजार से बढ़ कर 95 हजार हेक्टेयर हो जाएगी। औरंगाबाद जिला के आठ और गया जिले के चार प्रखंडों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

नदियों को जोड़ने की योजना

झा ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नदियों को जोड़ने की योजना में खास दिलचस्पी है। कोसी-मेची लिंक योजना को औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इस योजना पर होने वाले खर्च की 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। 40 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी। हालांकि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह कोसी-मेची को राष्ट्रीय परियोजना मान कर 90 प्रतिशत राशि दे। इससे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले के दो लाख, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले इस योजना पर चार हजार नौ सौ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था। अब इस पर अधिक राशि खर्च होगी। उत्तर बिहार की तीन नदियों-बागमती, कमला और कोसी को जोड़ने की योजना है। दक्षिण बिहार की नदियों-पुनपुन, किऊल और हरोहर को भी आपस में जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।